

एक नजर पिता ने बेटे पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। पुरानी बस्ती थाने में लाखों रुपये के हेरफेर के आरोप में एक पिता ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष महेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

अस्पताल चौहान निवासी अंगद चौरसिया ने तहरीर देकर बताया है कि उनका बेटा पंकज चौरसिया उनकी पान मेंटेरियल की दुकान चलाता है और खरबस भी करता है। आरोप है कि उसने धोखाधड़ी कर 20 लाख रुपये व दुकान का पैसा कुल 40 लाख लोन दो साल से अपने दोस्तों के साथ मिलकर हड़प लिया।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर पंकज चौरसिया व उसके दोस्त के खिलाफ आईपीसी 406 व 420 के तहत केस दर्ज किया है। विवेचक एसआई ओमप्रकाश मिश्र ने बताया कि इस प्रकरण में अन्य कई तथ्य भी सामने आए हैं। जांच कर उचित कार्रवाई होगी।

उडेल मर्डर मामले में होगी कुर्की

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कप्तानगंज थानाक्षेत्र के सेठा गांव में संत-बेटी की हत्या कर उसके शव को कमरे में तख्त पर रखकर जलने के मामले में करार चल रहे मुख्य आरोपी कमलेश उपाध्याय सहित अन्य आरोपियों पर न्यायालय की ओर से 82 की कार्रवाई करने का आदेश जारी हो गया है। शनिवार को पुलिस आरोपी के घर पर दुग्गी-मुनारी करा कर नोटिस चर्या कर सका है।

पुलिस कुर्की की के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा था। सीओ संजय सिंह ने बताया कि 82 की कार्रवाई करने का आदेश मिल गया है। मुख्य आरोपी कमलेश उपाध्याय ने न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए अजी दी थी लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। पुलिस लगातार उसकी कोशिश में छानबीन कर रही है। पुलिस तीनों आरोपियों के विरुद्ध कुर्की के लिए न्यायालय से शुक्रवार को आदेश जारी कराया है। न्यायाध्यक्ष के आदेश के क्रम में शनिवार को पुलिस आरोपियों के घर मुनारी करार नोटिस चर्या कर सका है।

मण्डी समिति के सचिव का

वेतन रोकने का आदेश

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अहालत ने कृषि मंडी समिति के सचिव का वेतन रोकने का आदेश दिया है। अग्रिम आदेश तक उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पुरानी बस्ती निवासी अफजल ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा था कि उसकी जमीनी मंडी परिषद में अधिग्रहित की गई है। 60 हजार रुपए प्रति बिस्वा की दर से भुगतान करने का आदेश कोन दे दिया था। भुगतान नहीं करने पर वसूली के लिए अफजल ने मुकदमा दाखिल किया है। इस मामले में अदालत ने बाबा मंडी समिति के सचिव को तलब किया था। अदालत में उपस्थित होकर सचिव ने भुगतान के लिए धार माह का समय मांगा था। इस अवधि के बीच भी किसान की जमीनी का भुगतान करनी ओर से नहीं किया गया। किसान की ओर से पुनः न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर कहा गया है कि बाबा मंडी के बाव भी मंडी समिति ने भुगतान नहीं किया। समिति के सचिव की कोर्ट के आदेश के प्रति धार लापरवाही मानते हुए अदालत ने सचिव का वेतन रोकने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

सैफ अली खान का संदिग्ध हमलावर हिरासत में

दुर्ग (आमा)। मुंबई में सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध को दुर्ग आरपीएफ हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरपीएफ ने शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से एक युवक को हिरासत में लिया है। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने आरपीएफ पुलिस को एक तस्वीर भेजी थी



जिसके आधार पर आरपीएफ पुलिस

डाक्टर से दुष्कर्म, हत्या में संजय दोषी करार

कोलकाता (आमा)। रियाल्टि सिलिल और किमिनल कोर्ट ने आरपी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में फैसला सुनाया। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी करार दे दिया। आरपी संजय रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे बताया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को अदालत में बोलने का मौका दिया जाएगा। अदालत सोमवार को सजा

सुनाएगी। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया।

महाकुंभ के लिए 25 बसों में 1500 यात्रियों को किया रवाना



—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। हरिया विधायक अजय सिंह द्वारा परगनागंज महाकुंभ में जाने के लिए क्षेत्र वासियों को निशुल्क निजी बस सुविधा मुहैया कराने का सिलसिला लगातार जारी है। कि यात्रियों और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को 1500 यात्रियों की 25 बसों को हरिया विधायक के खतमसराय से झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान बसदल्लुओं ने उत्साह के साथ धूप श्रीराम के नारे लगाए। विधायक ने यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं का विवरण भी श्रद्धालुओं में किया। पूर्व सांसद ने श्रद्धालुओं के सुखद और मंगल यात्रा का कामना करते हुए शुभकामना दिया। उन्होंने हरिया विधायक अजय सिंह की सरकावा करे हुए कहा कि विधायक द्वारा क्षेत्रवासियों को दी जा रही सुविधा प्रशंसनीय है। कि यात्रे में बताया कि क्षेत्र वासियों के लिए यह सुविधा महाकुंभ के अंतिम रणमत महाविचारित कि जा रही रहेगा।

—पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बढ़ाया विधायक अजय सिंह का डौलसा

निशुल्क महाकुंभ यात्रा के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यात्रियों के लिए रहने खाने इत्यादि की भी व्यवस्था निशुल्क कराई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में और बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ मेला में सम्मिलित हो सकें।

इस अवसर पर कृष्ण कुमार सिंह, महेश सिंह, कोरालत सिंह, मनीष सिंह लक्की, तेजबहादुर सिंह, इंद्र कुमार शुक्ल, विजय मिश्र काका, अखिलेश सिंह, मुलायम सिंह, रणजीत सिंह, रविंद्र सिंह, विनोद गुप्ता, अमरनाथ शर्मा, परमेश सिंह, निर्मल सिंह, दुर्गाेश, भिन्न, वीरू, विवेक, बड़े, शेर, आशु सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

बस्ती के 1814 गांवों में 116634 घरौनी का वितरण आडिटोरियम में 15 लोगों को मिला प्रमाण पत्र

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। शनिवार को स्वावलिय योजना के अंतर्गत जनपद के कुल 1814 गांवों में 116634 घरौनी का वितरण किया गया। अदल बिहारी प्रेक्षागृह सभागार में प्रमाणपत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वावलिय कार्य (घरौनी) वितरण कार्यक्रम उप उद्घोषण और उसी के क्रम में मुख्यमंत्री जी के स्वावलिय काई वितरण कार्यक्रम उप उद्घोषण का सजीव प्रसारण जनपद मुख्यालय के साध-साध समस्त तहसीली एवं विकासखंड मुख्यालय पर आयोजित स्वावलिय काई वितरण कार्यक्रम में किया गया।



जयप्रसद स्तर पर राज्य मंत्री विकास विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण औद्योगिक विभाग, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, कि यात्रे आने वाले दिनों में और बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ मेला में सम्मिलित हो सकें।

इस अवसर पर राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि प्रधानमंत्री द्वारा जन सामान्य को अपने अपने अधिकार के स्वावलिय का काई वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। इससे विशेष कर आबादी भूमि विवाद अर्थात स्वावलिय संबंधी विवादों का निराकरण हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि स्वावलिय योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वावलिय सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई, एक महत्वकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को लागू की उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार और स्वावलिय प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की भूमि को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने का कार्य किया है, जिससे उन लोगों को अधिकार मिले जिनके पास पारंपरिक रूप से भूमि का कोई दस्तावेज नहीं था। इस प्रमाणपत्र से ग्रामीण नागरिकों को न केवल कानूनी अधिकार प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें अपनी संपत्ति पर बैंक लोन लेने अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का भी अधिकार मिलता है।

कर दिया था। वहीं आरपीएफ प्रभारी संजीव सिन्हा ने बताया कि मुंबई पुलिस द्वारा एक फोटो दुर्ग आरपीएफ को भेजी गई थी, जिसके आधार पर शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल बोगी से संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया। युवक का नाम आकाश कैलाश कर्नाजिया है जो मुंबई का रहने वाला है। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में बैठकर बिलासपुर जा रहा था जहां से तिब्बत नेवरा में अपने परिचित के घर जाने की बात युवक ने आरपीएफ को बताया है। आरपीएफ ने मुंबई पुलिस को सिरिह 1 युवक की फोटो भेजकर पहचान कराई है।

ब्लैकमेल कर दुष्कर्म मामले में अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज —भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। जिले के परसरामपुर थानाक्षेत्र में एक युवती को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म की करने की बाबदायत मामले आई है। आरोप है कि आरोपी सत्यम ने सुपके से उनकी अरलीत फोटो बना ली। इसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया। एसआरओ परसरामपुर दिनेश कुमार कोर्ट ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सत्यम समेत दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घटना की विवेचना सीओ हरिया संजय सिंह स्तर से की जा रही है।

परसरामपुर थानाक्षेत्र की रहने वाली पीछित ने तहरीर आरोप लगाया है कि इसी थानाक्षेत्र के रहने वाले सत्यम ने उनकी अरलीत फोटो

उसने कई बार डककामा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। ऐसा करने से मना करने पर अपशब्द व जालिस्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित भी किया। आरोप है कि 26 अक्टूबर 2024 का दिन में दस जे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ आया और उनके ऊपर जलनशीली पदार्थ फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। कोर्ट के आदेश पर परसरामपुर पुलिस ने सत्यम व एक अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कर छानबीन शुरू कर दी है।

एक की सेवा समाप्त:11 परिचालकों को नोटिस

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। रोडवेज बस्ती डिपो में कार्यरत 11 परिचालकों को खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे परिचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जबकि एक परिचालक की सेवा समाप्त कर दी गई है।

एसआरएम बस्ती डिपो आयुष भटनगर ने बताया कि बरिष्ठ केंद्र प्रभारी ने रिपोर्ट दी है कि सिविला और आउटसोर्स के 11 परिचालक दिस्मर बाव से ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। इससे संचालन प्रभावित हो रहा। रिपोर्ट के आधार पर सिविल परिचालक बाबूलाका शर्मा, रमेशचंद्र राय, ऋषिकेश तिवारी, अमरेश सिंह, पुनीत सिंह, विजय विनाशक सिंह, नीलेश

अरविंद केजरीवाल पर हमला

नई दिल्ली. (आमा)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमले का दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि प्रवेश वर्मा के समर्थकों पर भी हमला किया गया है। प्रवेश वर्मा ने भी इस मामले को लेकर वीडियो शेयर किया है और दावा किया है जब लोगों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी।



संकेत। बीजेपी वालों, तुम्हारे इस

आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर कर दावा किया, भाजपा प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल पर ईट-पत्थर से हमला कर उन्हें कोर ऊपर पहुँचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार ना कर सकें।



ने अपनी गाड़ी से 2 युवाओं को

अमर आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मामले पर प्रेश कॉमेंट्री की और दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल की जान को बीजेपी के गुंडों से खतरा है।

अमर आदमी पार्टी के सामने भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी मामले का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और दावा किया है केजरीवाल ने दो युवाओं पर कार से टक्कर मार दी। उन्होंने कहा, सवाल पूछती जनता पर अरविंद केजरीवाल

अमर आदमी पार्टी के सामने भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी मामले का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और दावा किया है केजरीवाल ने दो युवाओं पर कार से टक्कर मार दी। उन्होंने कहा, सवाल पूछती जनता पर अरविंद केजरीवाल

गनेशपुर नगर पंचायत में बनेगा ओपेन जिम, स्टडी सेंटर : बोर्ड की बैठक में हुआ विमर्श

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। शनिवार को गनेशपुर नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक अथवा सोमवती चौधरी की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय पर सम्पन्न हुई। बैठक में साक स्काई प्रकाश ब्यवस्था, जलापूर्ति आदि विन्दुओं पर विचार कर महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। नगर पंचायत में पार्क और ओपेन जिम, स्टडी सेंटर का निर्माण कार्ये जाये पर सहमति बनी। अध्यक्ष सोमवती चौधरी ने कहा कि गनेशपुर नगर पंचायत को संसाधनों से लैश करने की दिशा में निरन्तर प्रयास जारी है।



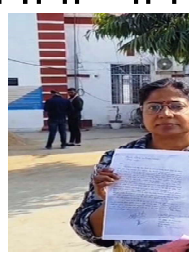
चौधरी ने कहा कि अध्यक्ष की ओर

बोर्ड की बैठक के बाद पूर्व विधायक एवं गनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दयाराम

ब्रह्मा प्रसाद, मो. करान, इन्द्रजीत यादव, मो. फारुक, सुनयन, गणेश कुमार, शिवनरायन, दुर्गाेश, पूजा, सुनीता देवी, मृग श्रीवास्तव, मो. मूलाकर के साथ ही दुर्गा प्रसाद चौधरी, मो. आरिफ, रिंकु यादव, सोनू सिंह, आशीष चौधरी, राजन पाण्डेय, महेश चौधरी, लालचंद चौधरी आदि उपस्थित रहे।

जमीन पर जबरिया कब्जे की कोशिश एसपी से लगाया न्याय की गुहार

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के अमरट उर्फ बैरिया निवासी अजिता त्रिपाठी पत्नी नीरज त्रिपाठी ने शनिवार को पुलिस अफसर को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। पत्र में कहा गया है कि गाटा संख्या 401, 402 मृप पर मालवीय व सहन तथा खाली जमीनी स्थित है जो नगर पालिका परिषद बस्ती में दर्ज है। उनके पूर्वजों ने रजिस्टर्ड बैनामा सन 1961 में लिया था।



व थाना कोतवाली को सूचना दी गई

विष्णु कृष्ण चन्द्र को प्रकाश चन्द्र पुत्रगण अजय कुमार व अनुराग पुत्र प्रेमचन्द्र उर्फ मुकेश व सहन व खाली जमीनी को अपना बाताकर जबरदस्ती कब्जा करने के प्रयास में है। इस सन्धन में स्थानीय पुलिस

किन्तु अभी तक कोई प्रमाणिकार्यवाही न होने से विपक्षियों का मनोबल बढ गया है। व लगातार गाटा नंबर आ गलियां देकर जमीन पर जबरिया

बाबा साहब की प्रतिमा उठा ले जाने के मामले में आशवासन पर धरना स्थगित

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कराये जाने, दीर्घायो के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर शास्त्री करीब पत्र चल रहा धरना अतिरिक्त उप जिलाधिकारी सुनिष्ठा सिंह के आशवासन के बाद स्थगित हो गया है। कलवारी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा को कलवारी पुलिस उठा ले गयी थी और अनेक ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर दिया था। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष था और वे भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतिरयन के नेतृत्व में न्याय को लेकर धरना दे रहे थे। आर.के. आरतिरयन ने बताया कि अतिरिक्त उप जिलाधिकारी सुनिष्ठा सिंह आशवासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर प्रकरण का निस्तारण करा दिया जायेगा और बाबा साहब प्रतिमा को स्थापित करने के साथ ही दर्ज मुकदमों को वापस कराने की दिशा में प्रयास कार्याये जायेगा। इसी कडी में गौर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत पतिला के पिपरा गोसाई निवासी छोट्ट पुत्र अक्षर को मुक्त दिखारकर पेशा बंद करा दिये जाते के मामले में सुनिष्ठा सिंह ने कहा कि मामले



की जांच करारकर पेशान दिलाता शुरू

निरणय के दौरान मुख्य रूप से ठाकुर प्रेम नन्दबशी, गुलजार गौतम, सुधीर प्रसाद चौधरी, राज सुनेर यादव, सुभारती बौद्ध, दीपक, रामचन्द्र, अमरजीत, राहुल आजाद, रोशन लाल, मेहीलाल, प्रहलाद गौतम, कृष्णाकर चौधरी, मो. जावेद, इफ्ताक, गिरिजाशंकर यादव, लक्ष्मी, रामरती, तेरसा, राधा गौतम, अंजु, प्रमिता लाल, अखिलेश्वरी, सोनी भारती, के साथ ही ग्रामीण और भारत मुक्ति मोर्चा पदाधिकारी शामिल रहे।

धरने के स्थगित होने के

"युद्धो अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 19 जनवरी 2025 रविवार

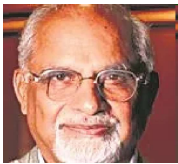
सम्पादकीय

इसाइल—हमास युद्ध विराम

यह सुखद ही कि करीब डेढ़ वर्ष से जारी इस्राइल—हमास संघर्ष खत्म करने के लिये युद्धविराम पर सहमति बन गई है। भले ही इस समझौते के लिये अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बीच संघर्ष समाप्ति का श्रेय लेने की होड़ हो, लेकिन गाजा के लोग जिस मानवीय त्रासदी से जूझ रहे थे, उन्हें जरूर इस कुछ राहत मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र के तमाम प्रयासों व मध्यपूर्व के इस्लामिक देशों की बार—बार की गई पहल के बावजूद अब तक शांति वार्ता सिरे न चढ़ सकी थी। जिसकी कीमत करीब पचास हजार लोगों ने अपनी जान देकर चुकायी। इस युद्ध से गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में जो तबाही हुई है, उससे उबरने में दशकों लग सकते हैं। निरसंदेह, इस्राइल व हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक समझौता यथार्थ में लागू होता न नजर आए, तब कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। हालांकि, अक्तूबर, तेईस में हमास के हमले से आहत इस्राइल कई मोर्चों पर लगातार युद्ध से थक चुका है, लेकिन अभी अरब जात उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। ऐसी आशंका इसीलिए भी है कि कई बार बातचीत अंतिम दौर पर पहुंचते—पहुंचते पटरी से उतरती रही है। बात और बात लगातार चलते रहे हैं। अब मिस्रियों में देखना होगा कि दोनों पक्ष समझौते के अमल के प्रति कितनी ईमानदारी से प्रतिबद्ध नजर आते हैं। हालांकि, अपने बंधकों की जल्द रिहाई को लेकर इस्राइल के विपक्षी राजनीतिक दलों व मंत्रिमंडल में भी मतभेद उभर रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद थक चुकी इस्राइली सेना को भी राहत देने की मांग की जाती रही है। बहरहाल, युद्ध विराम के प्रश्न पर इस्राइल व हमास के बीच सहमति से शांति की उम्मीदें प्रबल हुई हैं। जहां एक ओर अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन व नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए श्रेय ले रहे हैं, वहीं ईरान इसे फलस्तीनी प्रतिरोध की जीत बता रहा है।

दरअसल, हालिया समझौते में इस्राइली सेना की गाजा से वापसी, चरणबद्ध तरीके से इस्राइली बंधकों व फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा में पुनर्निर्माण पर सहमति बनी है। इसके साथ ही गाजा के विस्थापितों को वापस लौटने की अनुमति भी दी जाएगी। अभी गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया जाना है। दरअसल, सात अक्तूबर 2023 को हमास के क्रूर हमलों में इस्राइल के बारह सौ लोग मारे गए थे और करीब ढाई सौ लोगों को हमास के लड़ाके सोदेबाजी के लिये बंधक बनाकर ले गए थे। साफ था कि इस अपमानजनक घटना का इस्राइल प्रतिशोध लेगा, लेकिन संघर्ष करीब डेढ़ वर्ष तक चलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि, कुछ इस्राइली बंधक रिहा किए गए, कुछ युद्ध के बीच मारे गए, लेकिन बंधे बंधकों की रिहाई का भारी दबाव नेतन्याहू सरकार पर लगातार बना रहा। हमास समझौते स्वास्थ्य मंत्रालय दवा कर रहा है कि इस्राइली हमलों में अब तक पचास हजार लोग मारे गए हैं। संघर्ष में वास्तव में हमास के कितने लड़ाके मारे गए यह कहना कठिन है, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों—महिलाओं ने युद्ध में जान गंवाई। एक अनुमान के अनुसार गाजा संघर्ष में उपजी मानवीय त्रासदी में करीब बीस लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इस्राइली हमलों में अस्पताल—स्कूल भी निशाना बने, जिन्हें शरणार्थियों की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। इस्राइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध अपराध घटकों के आरोप लगाए गए। बहरहाल, जब लंबे समय के बाद शांति की स्थितियां बन रही हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विरादरी व संयुक्त राष्ट्र का दायित्व बनता है कि समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी की जाए। ताकि मध्यपूर्व में स्थायी शांति की राह मजबूत हो सके। निश्चित रूप से युद्ध शांति का विकल्प नहीं हो सकता। इस संघर्ष की शुरुआत भले हमास ने की हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत उन लोगों ने चुकाई, जो इसके लिये जिम्मेदार नहीं थे। हालांकि, इस बात को लेकर शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस समझौते से फलस्तीनी संकट का स्थायी समाधान हो सकेगा। बहरहाल, युद्ध की त्रासदी व मौसम की मार झेल रहे फलस्तीनियों को को कुछ राहत जरूर मिलेगी।

ट्रंप काल में पड़ोसी चीन की भूमिका



—टीएन निनान—

अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं, ऐसे में दुनिया मौलिक परिवर्तन के बीच फंस गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे शक्तिशाली देश भी अपनी राष्ट्रीय सम्प्रदाा सीमित बनाए रखने के लिए तैयार थे, जिसमें वे अधिकांशतः वैश्विक नियमों और सहकारी कार्रवाई का पालन करने के लिए सहमत थे। ऐसे नियम कई विषयों पर बनाए गए थे, केवल व्यापार और शुल्क ही नहीं, बल्कि परमाणु अस्त्र, समुद्रीय कानून और राष्ट्रीय सीमाओं की पवित्रता पर भी। आज दो कारणों से यह बदलने लगा है। पहला है चीन का उल्लंघन और उसके साथ—साथ हो रहा वैश्विक शक्ति—संपन्न राष्ट्रों में शक्तों के रूप में अभिव्यक्ति बनने पर उतारुता लोगों का उदय रु व्लादिमीर पुतिन, शो जिनपिंग और अब डोनाल्ड ट्रंप। इन दो घटनाक्रमों ने कुछ ऐसा फिर से ज्विज कर दिया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग नर चुका था, यानी महाशक्तियों द्वारा किया गए युद्ध, जिनका उद्देश्य नया इलाका हासिल करना है। इसका पर अमेरिकी युद्ध एक तरह से पूर्व—वैतानी भी थी। तौन साल पहले पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। ऐसा लगता है कि शो जिनपिंग ताइवान पर चीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब ट्रंप पनामा नहर और सीनैलैस को हासिल करने के लिए बल प्रयोग की धमकी दे रहे हैं।

अब बहुपक्षीय कार्रवाई करने की बजाय एकतरफा अभियान को प्राथमिकता दी जाने लगी है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन की घटती भूमिका एवं उपयोगिता के बीच जलज्वार परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित कार्रवाइयों का सिरे न बढ़ना दिखती है। भू—राजनीति सदा ही सत्ता को लेकर रही है, लेकिन अब यह नियमों से बेलागम हुई सत्ता विस्तार में बदलने लगी है। यह बात दक्षिण चीन सागर, गाजा का नरसंहार, तिब्बत के ऊपर एक विशाल नया बांध तीसरी दुनिया के सीधे संघर्ष से बचने वाले देशों को प्रभावित करने



भू—राजनीति सदा ही सत्ता को लेकर रही है, लेकिन अब यह नियमों से बेलागम हुई सत्ता विस्तार में बदलने लगी है। यह बात दक्षिण चीन सागर, गाजा का नरसंहार, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक विशाल नया बांध और तीसरी दुनिया के सीधे संघर्ष से बचने वाले देशों को प्रभावित करने वाले आर्थिक प्रतिबद्धों के मामले में एकदम सच दिखाई देती है।

करने के लिए बल प्रयोग की धमकी दे रहे हैं। अब बहुपक्षीय कार्रवाई करने की बजाय एकतरफा अभियान को प्राथमिकता दी जाने लगी है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन की घटती भूमिका एवं उपयोगिता के बीच जलज्वार परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित कार्रवाइयों का सिरे न बढ़ना दिखती है। भू—राजनीति सदा ही सत्ता को लेकर रही है, लेकिन अब यह नियमों से बेलागम हुई सत्ता विस्तार में बदलने लगी है। यह बात दक्षिण चीन सागर, गाजा का नरसंहार, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक विशाल नया बांध तीसरी दुनिया के सीधे संघर्ष से बचने वाले देशों को प्रभावित करने

साबित नहीं हुआ था, लेकिन लगातार नहीं कि इतिहास से मिले सबक बहुत ज़्यादा देर तक असरदार रहे। शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अतीत में नियम—निर्माण का बहुत बड़ा स्रोत यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, अब धरती का सबसे अधिकव्यवसायी देश बन गया है। फाइनेशियल टाइम्स के एक स्तंभकार ने अपने लेख में पूछा है : क्या अमेरिका एक बेलागम देश बन गया है। कोई नहीं जानता कि वह आगे क्या करने जा रहा है, और तो और इसके सहयोगी भी नहीं। यह सब दुनिया को कहीं ज़्यादा अशांत जगह बनागा, जहां पहले से बहुत सी अनिश्चितताएं और जोखिम व्याप्त हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो सहकारी एजेंडे बनाए गए थे, वे पश्चिमी प्रिमाण की प्रथाओं के कारण संभल हुए थे। ये कानून से समझौते पहले से मौजूद सत्ता संरचनाओं को दर्शाते थे और जिन्हें युद्ध से उभरे सबसे शक्तिशाली देश द्वारा पाला गया था। अगर यह विश्व व्यवस्था, जैसा कि बताया जा रहा है, यदि अब टूट रही है, तो हमें मूल कारण पर वापस जाना होगा। चीन के उदय से पश्चिम के लिए बनता खतरा, एक अभूतपूर्व गति

और पैमाने पर। पश्चिमी प्रतिस्पर्धा इस धारणा से प्रेरित है कि चीन ने स्वीकृत व्यापार नियमों का पालन नहीं किया, पश्चिम के औद्योगिकीकरण को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यवस्थित रूप से काम किया। पश्चिमी प्रौद्योगिकियों को भी चुनार्या हैदू लिहाजा उस पर व्यापार प्रतिबंध, बढ़ाया टैरिफ, प्रौद्योगिकी तकनीक देने से इनकार इत्यादि अनेक अन्य उपाय किए जाए।

लेकिन शायद यह करने में बहुत देर कर दी। चीन की औद्योगिकी श्रेष्ठता को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। पिछले साल इसने अमेरिका से 12.6 गुणा अधिक स्टील, 22 गुणा अधिक सीमेंट और तीन गुणा अधिक कारों बनाई— जिनके इलेक्ट्रिक मॉडलों के साथ यह अब कार बाजार में जापानी और जर्मनी के वर्चस्व को पछाड़ने की हैसियत में आ चुका है। सकल वैश्विक जलपोत उत्पादन में चीनी शिपयार्ड का हिस्सा आधे से अधिक है। 2030 तक, चीन का विभिन्न क्षेत्र समूची पश्चिमी दुनिया के कुल उत्पादन से अधिक होने का अनुमान है।

ये शक्तियां केवल तभी तक उपयोगी हैं यदि चीन अपनी पहुंच विश्व बाजारों तक जारी रख पाए, जिसे घटाने की उन्नततरतों को चीन जा रही है। फिर भी चीन ने 2024 में रिफाईं व्यापार अभिषेक का अन्याय किया, और डिप्लोमसी डौल अर्थव्यवस्था बनने के कारण पर है। कुछ क्षेत्रों में यह तकनीक के मामले में पश्चिमी मुकों से आगे निकल गया है। लेकिन अब चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर बाधागत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

वास्तविकता जिससे निपटा जाना चाहिए वह यह है कि पश्चिम मुक्त जितना अधिक खतरा महसूस कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी वे अपने उन नियमों को तज रहे हैं जिनका इस्तेमाल कर उन्होंने कभी खेले किया था। नई दुनिया में, हर देश अपने हित पर केंद्रित है, और इसके लिए शक्ति प्रयोग ज़ाबज मानता है। हकीकत है कि हर देश अपना रक्षा

बजट बढ़ा रहा है, हम उम्मीद करें कि इससे संघर्ष न बढ़े। भले ही इसे टाला जा सकता है, लेकिन पुरानी दुनिया वापस नहीं आएगी। लेकिन क्या नई दुनिया नए नियमों के लिए सममत हो सकती है?

जिस प्रकार चीजें चल रही हैं, इससे पहले कि मुक्त वार्ता के लिए राजी हो, वैश्विक शक्ति धुरी में बदलाव के लिए खेल होकर रहेगादू तब जाकर, महाशक्तियां आक्रामकता या आक्रामक मुद्रा के माध्यम से अपनी—अपनी हदों की आजमाइश करेगी। एक नया तरीका निकलकर आ सकता है। यह यदि वह मान भी लिया जाए कि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से चीन अमेरिका को पछाड़ने में कान्याव हो जाए, तो भी उसे पूरी तरह वहां से खदेड़ नहीं पाएगा, और रूस को वह हलत जाएगा जो वह चाहता है रू अपने प्रमुख क्षेत्र वाला आसपास का इलाका। यह एक विश्व व्यवस्था होगी या नहीं, यह इतना स्पष्ट प्रश्नों के उत्तरों पर निर्भर करता है मौजूदा शाक्तों की जगह कौन लेगा, क्या महाशक्तियां जीने और जीने देने के संभवतः पर सहमत होंगी और मिस्रम दर्जे की शक्तियों की भूमिका रहेगी।

हमें सुरक्षा परिषद जैसी वर्तमान वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर ब्यान देना होगा। आवर्ध रूप से, पश्चिम को वोटों को समाप्त कर देना चाहिए और यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को तथा विश्व बैंक में प्रचलित मतदान आधारित व्यवस्था को अपनाना चाहिए। इससे आज के वोटों समुच्चन मूल्य अंतर्राष्ट्रीय राय के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगे। व्यापार जगत में, बुरी तरह हाली वैश्विक व्यापार नियमों की तुलना में बहुपक्षीय व्यवस्था के भी संभावना तब अधिक होगी। अफ्रीकी महाद्वीप के गरीब देशों के लिए वैश्विक समझौता जरूरी है। बाहेत तो, इस मामले में मध्यम दर्जे की शक्तियां कतर से सीख ले सकती हैं और चीन में सुधार लाने को म्क यथक्ता की भूमिका निभा सकती हैं। —लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सत्ता की बैसाखी से बदलते नेताओं के सुर

योगेन्द्र योगी—

बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलित प्रदेश के युवाओं की मांग पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी आश्चर्यजनक नहीं है। दरअसल माजपा न सिर्फ बिहार नीतिश सरकार में शामिल है, बल्कि केंद्र में भी उसी की बैसाखियों पर टिकी है। ऐसे में मुझ जनहित का हो या न हो, इससे माजपा को फर्क नहीं पड़ता। इससे पार्टी के उसूलों पर भी आघात नहीं आती। इसी भाजपा ने राजस्थान में कांग्रेस की अशां गणतंत्र सरकार के खिलाफ पेपर लीक प्रकरणों में विरोध प्रदर्शनों में कोई कोर—कसर बाकी नहीं रखी। यह दोहरा चरित्र अकेले भाजपा का हो ऐसा नहीं है। जिस प्रदेश या केंद्र में जिस भी दल की सरकार होती है, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी का रवैया ऐसा ही होता है। केंद्र में कांग्रेस शासन के दौरान सहयोगी दलों के धपन—धोलते इसका प्रमाण रहे हैं। सत्ता के लिए गठबन्धन की मजबूरी से ऐसा करना देश की राजनीति का चरित्र बन गया है। सत्ता में होने पर पार्टी को कुछ गलत नजर नहीं आता और विश्व में आते ही मुँह और तरीके बदल जाते हैं।

बिहार में 13 दिसंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की 70वीं पीठी परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दिन से ही अनेकवीं परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इसे रद्द करने फिर से कराने की मांग की। अनेकवींयों ने आरोप लगाते फिर पटना के बापू एजमा सेंटर पर छात्रों को पेपर देने से मिला था और पेपर की सील पहले से खुली हुई थी। छात्र प्रदर्शनकारियों के पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करते पर पुलिस दवाकर किए गए लाठीचार्ज और वाहन फेंकना इस्तेमाल ने छात्रों और उनके संगठनों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। बिहार की तरह राजस्थान भी कांग्रेस शासन के दौरान पेपर लीक प्रकरणों के कारण सुर्खियों में रहा है। राजस्थान की पूर्ववर्ती परीक्षा सरकार में हुई प्रतियोगिता कांग्रेसों में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आए। सब इस्तेवर



भरती, सीएसओ भरती, लाइबरेशन भरती और वरिष्ठ अध्यापक भरती सहित कई परीक्षाओं को पेपर लीक होने के खुलासे हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से व्याख्याता भरती 2022 की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। पेपर लीक मामले में उलझी सब इस्तेवर भरती 2021 की ओर लेकर प्रदेश के लाखों युवाओं में हर ताजा अपडेट का झुंझार है। पेपर लीक और उभी अभ्यर्थियों के जरिए सैकड़ों युवाओं ने नौकरी हासिल कर ली है। इस मामले को जांच करने वाली एएसओ ने भी व्यापक स्तर पर पेपर लीक होना माना और इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश पुलिस मुख्यालय को भेजी थी। पुलिस मुख्यालय और मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने भी परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने इस भी परीक्षा को अभी तक रद्द नहीं किया।

राज्य सरकार ने एसआई भरती 2021 में चयनित सभी ट्रेनी सब की परीक्षा के आगामी प्रश्नपत्रों को रद्द करा दिया। सरकार ने यह निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लिया। एक साल की लंबी एसएससाइज में अभी तक 50 सब इस्तेवरपड पकड़े गए। आधुनिकी के सदस्य पकड़े गए। आधुनिकी के बाद यह है कि राजस्थान में भाजपा सरकार कैंटी एके कैबिनेट मंत्री अपनी ही सरकार के फंसलों पर सांजनीतिक रूप से सवाल उठा रहे हैं। कृष्ण मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सब इस्तेवरपड मंत्री परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार भाजपा अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं कर सकी। अनुसूचित माने जाने वाली भाजपा की मजबूरी है कि मीणा के खिलाफ पार्टी और



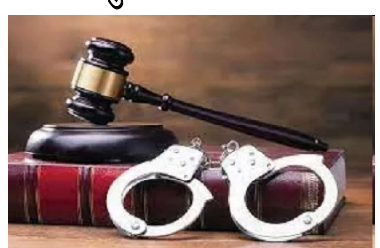
—डॉ. सुधीर कुमार—

भारतीय बार काउंसिल (बीसीआई) कानून विश्वविद्यालयों में कानूनी सहायता वकीलों की स्थापना और संचालन को अनिवार्य मानती है। इन वकीलों का उद्देश्य छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ—साथ व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। उन्हें गरीबों तथा वंचितों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है। बीसीआई इन वकीलों की नियमित निगरानी करती है, ताकि छात्रों को उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मिल सके। कानूनी सहायता वकील न होने पर शिक्षा संस्थानों पर जुमाना, शो कौन नोटिस, अनुसंधानकार्य कार्रवाई या मान्यता देकर करने जैसी कड़ी कार्रवाईयों की जा सकती है।

लीगल एड वकीलन ऐसे केंद्र होते हैं, जहां कानून के छात्र ज़रूरतमंद लोगों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं जिससे छात्रों को वास्तविक जीवन के कानूनी मुद्दों से निपटने का अनुभव मिलता है। वे कानूनी प्रणाली को गहरे से समझते हैं। वे वकीलन परिवारिक, भूमि, श्रम विवाद जैसे विभिन्न मामलों में मदद करते हैं। भारत में कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लीगल एड वकीलन कार्यक्रम किए गए हैं। सरकार भी वित्तीय सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से इनका समर्थन करती है।

लीगल एड वकीलन छात्रों को अपने कानूनी ज्ञान को सैद्धांतिक से परे वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने का अग्रुत अवसर प्रदान

विधि क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव और सैद्धांतिक ज्ञान



करते हैं। वहां वे विभिन्न कानूनी मामलों से निपटते हैं, लोगों को कानूनी सलाह देते हैं, और कानूनी रिवादों को व्यावहारिक अनुभव के साथ समझाते हैं। इसमें भागीदारी से छात्र सामने सेना के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। यहां उन्हें वकीली, व्यावहारिक और अन्य कानूनी पेपर्स से वातावरण का मौका मिलता है, जिससे उनका नेटवर्क मजबूत होता है। इस अनुभव से छात्रों को अपने भविष्य के कार्य के लिए व्यावहारिक तैयारियां मिलती हैं। एक कॉर्पोरेट कानून का छात्र छोटे व्यवसायों को कानूनी सलाह देकर कॉर्पोरेट कानून के पदरुखों को समझ सकता है।

कानूनी सहायता वकीलन में छात्रों को शामिल करना आवश्यक है, जिससे उन्हें वास्तविक मुकदमे और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके। अनुभवी अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन, कानूनी प्रक्रियाओं और नैतिक मानदंडों की समझ जरूरी है। वकीलन संचालकों को समाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इसके अलावा, वकीलन को आधुनिक संसाधनों जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और कानूनी पुस्तकालय से सुसज्जित किया जाना चाहिए। इसमें शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें छात्रों के साथ स्थायी संबंध स्थापित करना चाहिए, ताकि वे अपनी समस्याओं को खुलकर साझा कर सकें। शिक्षकों को प्रायोगिक शिक्षण पद्धतियों, जैसे मॉक कोर्ट और वकीलन लीगल एडुकेशन

के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देना चाहिए। वे छात्रों को यह समझाएं कि लीगल एड वकीलन समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षकों को अपने ज्ञान को अपडेट रखना चाहिए, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और उन्हें नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों को पारंपरिक बजट और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता प्रुतिष्ठित करना, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और विभिन्न प्रकार के कानूनी मुद्दों के लिए कार्यक्रम विकसित करना चाहिए। इसके अलावा, विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना, जागरूकता अभियान चलाना, नियमित मूल्यांकन करना और आयाकों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। तकनीकी का उपयोग और कानूनी सेवा प्रतिक्रियाओं के साथ सहभाग्य करके भी इन तकनीकों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

लीगल एड वकीलन की प्रभावी निगरानी के लिए नियमित बैठकें, विद्यार्थियों से प्राप्ति रिपोर्ट लेना आदि महत्वपूर्ण उपाय हैं। इन उपायों से वकीलन के उद्देश्यों का साथ, विद्यार्थियों का विकास और लोगों की सुविधि सुनिश्चित हो जा सकती है। —लेखक कुशोत्र विधिविद्यालय के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में यमुना
महासंगम शुरू हो गया। स्वामित्व
योजना के तहत धरनी वितरण
कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य की
कीर्तिचक्र सिंह ने केंद्र बड़े बयान
दि। अरविंद केजरीवाल ने कहा था
कि हम यमुना नदी सीही नहीं कर
पाए। शुद्ध जल और स्रोत जैसी
सड़क नहीं बना पाए। लेकिन मुझे

द० हाकिम	bhartiyaabasti@gmail.com
----------	--------------------------